



(23) न्यायालय - माननीय राजस्व में इन महोदय, ग्राम प्रौद्योगिकी के द्वारा

माननीय राजस्व में इन महोदय, ग्राम प्रौद्योगिकी के द्वारा

प्रौद्योगिकी

/2017 निर्गम

I/निगरानी/विविधा/भूमि/2017/3860
श्रीमति शीलबेंडी पत्नि अमोतसिंह तोधी,
निवासी ग्राम - सुआड़ी, तह - गुलाबगंज,
जिला - विविधा. —— निगरानीकर्ता

बनाम

1. दीनदयाल पुत्र भैयालाल लोधी, निवासी -
ग्राम - सुआड़ी, तह - गुलाबगंज, जिला -
विविधा.

(6) 2. श्रीमति शीलबेंडी पत्नि राममोहन कपूर,
कृष्णगंज ग्राम - सुआड़ी, तह - गुलाबगंज,
जिला - विविधा, हाल मुकाम - पंचील
पार्क एम्स सड़हिलाबाद, जिला - गांधियाबाद
[उ.प्र.] . —— रिस्पॉन्डेंट

लगिभारक श्री..... के संस्थान गणपति
द्वारा आज दिनांक १५.१०.११
को प्रेषित
अधिकारी

निगरानी अंतर्गत धारा - 50 म.प्र. भू. रा. संहिता, 1959

माननीय महोदय,

तेबा मैं यह निगरानी अधिकारी न्यायालय श्रीमान्
एस. डी. जौ. महोदय, ग्यारहपुर, जिला - विविधा के राजस्व प्रौद्योगिकी 76
अपील 2016-17 दौली बाई बनाम दीनदयाल आदि में पारित आदेश

क्षितिक 15.9.17 के विरुद्ध अंदर म्याद पेशी की जा रही है।

निगरानी के तथ्य :-

1. यह कि, निगरानीकर्ता ग्राम - सुआड़ी की निवासी
होकर ग्राम - सुआड़ी स्थित भूमि सर्वे क्र. 39 रकमा 0.219 है। स्वत्व
एवं आधिकार्य धरी कृष्ण है, इस भूमि को निगरानीकर्ता ने वर्ष 1993
में रिस्पॉन्डेंट 2 के भाई एवं आम मुक्तयार श्री शिखर द्वारा पुत्र दौलीवाल

—2

(निभू)

दौलीवाल

दोलीबाई / दीनदयाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/विदिशा/भूरा०/2017/3860

जिला – विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.10.2017	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 76/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आलोच्य आदेश द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपर कलेक्टर विदिशा के पत्र दिनांक 19.09.2017 के प्रकाश में प्रकरण अपर कलेक्टर को प्रेषित किया गया है। प्रकरण में उनके द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है। आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर अभी अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p> 	